

मुख्य समाचार :-

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा—देशभर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं है।
- एलपीजी गैस की शत प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करवाने के देहरादून में क्विक रिस्पांस टीम ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा किनारों और बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
- और.. प्रदेश में 20 मार्च तक बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना।

एलपीजी बुकिंग

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी बुकिंग में गिरावट आई है। लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई, जबकि इस महीने की 13 तारीख को लगभग 88 लाख बुकिंग दर्ज की गई थीं। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भी प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं और अब उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी का कोई मामला सामने नहीं आया है और पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। मंत्रालय ने लोगों को घबराहट में खरीदारी न करने की सलाह दी है।

इस बीच, मंत्रालय ने पीएनजी और एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया है। पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या वितरकों से एलपीजी रिफिल करने की अनुमति नहीं होगी।

एलपीजी गैस

देहरादून जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में कल जिले की सभी गैस एजेंसियों पर एलपीजी गैस का वितरण केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ओटीपी आधारित व्यवस्था के तहत किया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य गैस एजेंसियों व गोदामों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करना और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना है।

जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम— क्यूआरटी ने सक्रिय रूप से अपने-अपने क्षेत्रों में आवंटित गैस एजेंसियों का भ्रमण कर गैस की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। भ्रमण में सुनिश्चित किया गया कि गैस सिलेंडर का वितरण केवल होम डिलीवरी और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से ही किया जाए। सभी गैस एजेंसियों एवं गैस गोदामों पर होम डिलीवरी से संबंधित फ्लैक्स व सूचना पट्ट चस्पा किए गए।

गैस आपूर्ति अथवा वितरण से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए नागरिक जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1077, 0135-26 26 06 6, 01 35-27 26 06 6 तथा व्हाट्सएप नंबर 75 34 82 60 66 किया है।

गैस

वहीं एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने तथा शत प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करवाने के देहरादून जिले में क्षेत्रवार गठित क्विक रिस्पांस टीम ने गैस एजेंसियों के निरीक्षण किया। इस दौरान एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति समेत अन्य सभी गतिविधियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल जिले में गैस आपूर्ति व वितरण बैकलॉक की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

इस बीच आदेशों उल्लंघन करते हुए शहीद हीरा गैस एजेंसी शिमला बाईपास रोड के सिलेंडर जिला प्रशासन ने जब्त कर लिए तथा गैस एजेंसी स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।

उधर हरिद्वार पूर्ति निरीक्षक कनखल ने मै० पुष्पक गैस सर्विस, (बी०पी०सी०) कनखल के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए, स्पष्टीकरण का जवाब न उपलब्ध होने की दशा में एजेंसी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाए जाने के लिए कहा गया है।

फास्टैग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास के लागू शुल्क को 75 रुपये बढ़ाकर तीन हजार 75 रुपये करने की घोषणा की है। बढ़ा हुआ शुल्क पहली अप्रैल से लागू होगा। ये पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है।

पद्म पुरस्कार

सरकार ने पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएं आमंत्रित की हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी।

गंगा नदी

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा नदी के किनारों और बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने केंद्र सरकार से गंगा के पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन संबंधी अधिसूचना के कार्यान्वयन और क्रियान्वयन के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी देने के लिए कहा है।

गंगा घाटी के कई राज्यों को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा है कि इस मुद्दे पर व्यक्तिगत मामलों से परे व्यापक जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि अधिसूचना को प्रभावी ढंग से लागू करने और नदी के किनारों और बाढ़ के क्षेत्रों को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण अदालत से क्या निर्देश चाहता है।

मौसम

मौसम विभाग ने 20 मार्च तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के अधिकांश स्थानों पर तेज बारिश और 3 हजार 200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान है।

इस दौरान ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने लोगों को मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की सलाह दी है।

इस बीच, कल रात को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं, केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय लोक अदालत

हरिद्वार जिले में आयोजित इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में 1879 वादों को निपटारा किया गया। लोक अदालत में चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना कलेम, पारिवारिक विवाद, सिविल वाद, श्रम विवाद, विद्युत अधिनियम एवं बैंक रिकवरी, शमनीय प्रकृति के मामलों को प्राथमिकता दी गई, जिससे न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के बोझ को कम करने में बड़ी सफलता मिली।

प्रभारी सचिव ज्योति बाला ने बताया कि इस आयोजन में कुल 15 करोड़ से अधिक समझौता राशि का सेटलमेंट हुआ।

निरीक्षण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव न्यायाधीष प्रदीप कुमार मणि के नेतृत्व में न्यायिक एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के एक दल ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा इलाके में प्रभावित परिवारों के लिए प्रस्तावित पुनर्वास शिविर स्थलों का निरीक्षण किया।

इस दौरान न्यायाधीष श्रीमणि ने बताया कि गत 24 फरवरी को एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के तहत यह कार्यवाही की जा रही है।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

पांच राज्यों में चुनाव के ऐलान की खबर को सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर प्राथमिकता दी है... हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है— पं.बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में 9 से 29 अप्रैल के बीच मतदान, दैनिक जागरण लिखता है— बंगाल में दो चरणों में होगा चुनाव।

जनसमस्याओं के निस्तारण में कोताही न बरतें अधिकारी— इस शीर्षक के साथ अमर उजाला खबर में लिखता है—कृष्ण धामी ने खटीमा में अपने निजी आवास और हेलीपैड रक सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान के लिए निर्देश।

रुद्रपुर में एनसीईआरटी की नकली किताबें मिली— इस शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान समाचार पत्र खबर में लिखता है— पुलिस, तहसील और शिक्षा विभाग ने गोदाम पर मारा छापा, चार करोड़ की किताबें बरामद।

और उत्तराखंड में बदले मौसम की खबर पर दैनिक जागरण लिखता है— चारधाम और ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, मैदानी इलाकों में तेज वर्षा, मौसम की करवट से फिर ठंड का एहसास।